an>

Title: Need to remove the shortcomings in the agreement between Jharkhand and Bengal of 1978.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूँ।

19 जुलाई, 1978 का एक एग्रीमेंट है, जो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी तथा बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी के बीच हुआ था। उस वक्त जो बिहार का समझौता हुआ था, वह अब झारखण्ड का समझौता हो गया है। मैं आपको बताऊँ कि झारखण्ड के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, उसे मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ।

हमारे यहाँ मयुराक्षी डैम, पंचेत, मैथन और दामोदर वैली कारपोरेशन हैं। ये सभी झारखण्ड में हैं। इनका पानी हमारे यहाँ स्टोर होता है और मैक्सिमम पानी का यूज़ वेस्ट बंगाल सरकार करती है। यहाँ तक कि दामोदर वैली कारपोरेशन जो पावर बनाता है, उसका हेड क्वार्टर भी वेस्ट बंगाल में ही है और हमको उसके ऊपर निर्भर करना पड़ता है कि वह हमको बिजली देगा या नहीं देगा। उसी समझौते के आधार पर, रवीन्द्र कुमार पाण्डेय जी बैठे हैं, यह मामला इनके क्षेत्र से भी जुड़ा है और यह मामला लगातार 15 साल से उठाते आ रहे हैं।...(व्यवधान) उसको बैल पहाड़ी बराकर नदी में एक डैम बनाना था और वर्ष 1978 से आज तक वह डैम नहीं बन पाया है।...(व्यवधान) जो कोनार डैम बनना था, उसको वर्ष 1980 में कमीशन होना था, वह भी नहीं हो पाया है।...(व्यवधान)

महोदया, मैं संथाल परगना से आता हूं। यह एग्रीमेंट कहता है- construct the Siddheswari-Noonbeel dam in West Bengal. यह वर्ष 1978 में कहा गया है कि उसको बनाना है, लेकिन आज तक वह डैम नहीं बन पाया है।...(व्यवधान) उसी तरह से उनको काली पहाड़ी डैम बनाना था और इसके अलावा चार डैम और बनाने थे। संथाल परगना और पूरे झारखण्ड में एक साल बारिश होती है और दो साल सूखा होता है।...(व्यवधान) हमारा पानी है और हमारी जमीन है। बैराक्षी का पानी, पंचेत का पानी और मैथन के पानी को वेस्ट बंगाल यूज़ कर रहा है। लेकिन वह हम को डैम बनाकर नहीं दे रहा है।...(व्यवधान) वेस्ट बंगाल सरकार को अपने खर्च पर सिद्धेश्वरी-नूनबैल, बैल पहाड़ी पर बराकर और काला पहाड़ी डैम बनाने थे और चार डैम बनाने थे।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि हम लोगों को बचाइए।...(व्यवधान) हमारे देवघर में डेढ़ हजार फीट पर पानी मिलता है और लोग बिना पानी के मर रहे हैं, उसके लिए भारत सरकार को उपाय करना चाहिए और इस एग्रीमेंट को री-डू करना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय,

श्री शरद त्रिपाठी और

श्री भैरो प्रसाद मिश्र को श्री निशिकांत दूबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : अध्यक्ष जी, मैं इस को सपोर्ट करता हूं। यह पिछड़ा हुआ इलाका है और यहां दोनों सरकारों के सहयोग से डैम बनना चाहिए।...(व्यवधान)